

1. स्कूल शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर दो महीने के लिए लगाई गई रोक : मामले का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी सभी पक्षों के साथ करेगी बैठक।
2. प्रदेश में 17 जिलों के 1500 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 24 घंटे में पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के दिये निर्देश।
3. लखनऊ के पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर समेत अन्य क्षेत्रों में नहीं तोड़े जाएंगे घर : मुख्यमंत्री ने कहा— हर निवासी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
4. केन्द्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आज प्रयागराज में हमारा संविधान—हमारा सम्मान अभियान के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन को किया संबोधित।

और

5. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर छूट अक्टूबर 2027 तक बढ़ो : दो पहिया ई वाहन की खरीद पर पांच हजार और चार पहिया पर एक लाख रुपये की मिलेगी सब्सिडी।

---

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर दो महीना के लिए रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षकों के एक

प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद आज यह आदेश दिया। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में यह कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी। शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की समस्या का हल ढूंढने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याएं सुनकर शासन को भेजें ताकि उनका समाधान किया जा सके। योगी सरकार ने प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे। आठ जुलाई से शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे।

---

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि लखनऊ में कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर समेत अन्य क्षेत्रों में घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज प्रभावित

परिवारों के भय और भ्रम का समाधान करते हुए कहा कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमि पर बने भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हांकन के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आमजन में भय और भ्रम फैला है, इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें। उनका भय और भ्रम दूर करें।

---

प्रदेश में 17 जिलों के 15 सौ से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के शहरी इलाके भी बाढ़ से ग्रस्त हैं। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत, लखीमपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर, बदायूं, देवरिया, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली और बाराबंकी जिलों के कई

गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में 14 लाख से अधिक लोग आय हैं, जिनमें से पांच लाख से अधिक लोगों की फसलें, घर और सामान समेत अन्य संपत्ति नष्ट हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उधर, वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अगले आदेश तक गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित 48 गांवों में 91 नाव सहायता के लिये लगाई गई है। पीलीभीत में साढ़े सात हजार से अधिक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। हरदोई में 133 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 48 बाढ़ चौकियां और 105 शरणालय बनाये गये हैं। शाहजहांपुर में राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। राशन संबंधित शिकायत मिलने पर एसडीएम सदर को तत्काल राशन बंटवाने के निर्देश दिये।

---

नीट पेपर लीक मामले में केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कल रात हज़ारीबाग के गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हज़ारीबाग से अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गये हैं।

---

वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जल्द इमरजेंसी मेडिकल रूम स्थापित किया जाएगा। इसमें 24 घंटे चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट की तैनाती होगी। कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर गौरव दीक्षित ने बताया कि इस इमरजेंसी रूम में एक रुपये में पर्चा बनवाकर यात्री इलाज प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर बेसिक मेडिकल जांच की व्यवस्था भी रहेगी। बाइट.....

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बिजी स्टेशन है तो आने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनमें कोई इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की कभी जरूरत है तो उनको अटेंड करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे द्वारा एक प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलकर एक एम ओ यू किया गया है जिसके तहत एक इमरजेंसी मेडिकल room हमारे यहाँ एब्लिश किया जा रहा है जिसमें कि एक रुपये देकर OPD में जो वहाँ पर round the clock doctor और paramedical staff रहेंगे वो कोई भी medical समस्या होने पर passenger उनको दिखा सकते हैं। basic जो medical जांचें होती है जैसे blood sugar है, BP है, ECG वगैरह वहीं पर हो जाएगा और कोई भी अगर advance जरूरत होगी तो वो किसी बाहर के doctor को refer भी कर सकते हैं।

---

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

अभी वक्त है एक ब्रेक का

जिंगल

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

---

केन्द्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आज प्रयागराज में हमारा संविधान—हमारा सम्मान अभियान के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये हमारा संविधान—हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया। इस मौके पर श्री मेघवाल ने कहा कि हमारा संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। यही वजह है कि आज हम विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता को दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना है।

कार्यक्रम के दौरान माय गव की ओर से संविधान से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

---

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में 19 करोड़ 61 लाख रुपये की छह विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत मां विन्ध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल पर सुविधाओं के विकास, चिन्दलिख गहरवार में हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण व पर्यटन विकास का काम, नारायणपुर में बैकुंठ महादेव स्थल के पर्यटन विकास का काम समेत अन्य काम किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विन्ध्याचल एक ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत विन्ध्य क्षेत्र में पर्यटन से सम्बन्धित सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन के माध्यम से इस क्षेत्र की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना चाहती है। अगर क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

---

सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी देने की व्यवस्था है, ताकि ई वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। यह सब्सिडी दोपहिया वाहनों पर पांच हजार रुपये और चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये है। अभी तक इलेक्ट्रिक

वाहन खरीद पर छूट सिर्फ एक साल के लिए थी, जो अक्टूबर 2023 में खत्म हो गई थी। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक, दोपहिया और चार पहिया वाहनों को सब्सिडी का लाभ अक्टूबर 2027 तक मिलेगा।

(समाप्त)